शुगर मिल मालिकों ने किस्तों में FRP पेमेंट की मांगी इजाजत

मिलों ने यह मांग ऐसे समय में की है जब देश में फिर से रिकॉर्ड शुगर प्रॉडक्शन होने जा रहा है

[जयश्री भोसले | पुणे]

कर्नाटक और महाराष्ट्र के शुगर मिल मालिकों ने सरकार से फेयर एंड रम्यूनरेशन प्राइस (एफआरपी) को कई किस्तों में देने की इजाजत मांगी है। कानून के मुताबिक एफआरपी का भुगतान एकसाथ किया जाता है। मिल मालिकों ने यह मांग ऐसे समय में की है, जब भारत फिर से रिकॉर्ड शुगर प्रॉडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ, ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के दाम कम बने हुए हैं।

इंडस्ट्री के मुताबिक, 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे शुगर सीजन 2018-19 में भारत 355 लाख टन शुगर का उत्पादन करेगा। मौजूदा शुगर सीजन में इसके 322.5 लाख टन रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने मिलों के लिए शुगर की मासिक बिक्री की सीमा तय करने के एक सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसके तहत सभी मिलों को शुगर कोटा आवंटित किया गया था। इसके लिए शुगर की मिनिमम सेलिंग प्राइस 29 रुपये प्रति किलो तय की गई थी। हालांकि, इन उपायों से मिल लेवल पर

- इंडस्ट्री के मुताबिक, 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे शुगर सीजन 2018-19 में भारत 355 लाख टन शुगर का उत्पादन करेगा। मौजूदा शुगर सीजन में इसके 322.5 लाख टन रहने का अनुमान है

कीमत को 30 रुपये प्रति किलो तक रखने में मदद मिली है, लेकिन इससे देश में शुगर स्टॉक में काफी बढ़ोतरी हुई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के अनुमान के मुताबिक अगर देश से शुगर का एक्सपोर्ट शुरू नहीं होता है, तो 2018-19 सीजन के अंत में 190 लाख टन का स्टॉक बचा रह जाएगा।

साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (कर्नाटक) के प्रेसिडेंट आनंद रेड्डी ने बताया, 'कई किस्तों में पेमेंट की इजाजत मिलने से सभी किसानों को कम से कम एक किस्त का भुगतान हो पाएगा।' एसोसिएशन ने कर्नाटक सरकार को लिखे एक लेटर में कहा है, 'मासिक कोटा तय करने और एक्सपोर्ट पर मिलने वाली सब्सिडी में देरी से शुगर फैक्टरियां फिलहाल शुगरकेन एक्ट के मुताबिक एफआरपी का एकसाथ पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हैं।' नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज (NFCSF) ने भी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज (सीएसीपी) के सामने इस मामले को उठाया है। NFCSF के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश ने बताया, 'हम चाहते हैं कि सीएसीपी गुजरात मॉडल को अपनाए। वहां गन्ना की कीमतों का 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है।

इससे किसानों को भी अलग-अलग त्योहारों के वक्त पैसा मिलता है और मिलों को भी वित्तीय घाटा नहीं सहना पड़ता है क्योंकि भुगतान के लिए बैंकों से कर्ज नहीं लेना होता। इस तरह से गुजरात के किसानों को पूरे देश में गन्ने की सबसे अधिक कीमत मिलती है।' हाल ही में पुणे में हुई एक बैठक के दौरान महाराष्ट्र के शुगर मिल मालिकों ने भी एफआरपी पेमेंट 2 से 3 किस्तों में करने की इजाजत मांगी थी।

The Economic Times · 31/8/18